

an&gt;

Title: Issue regarding import of crude oil from Iran.

**श्री मनीष तिवारी (आनंदपुर साहिब):** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। दुनिया का एक हिस्सा है, जिसे दक्षिण एशिया कहते हैं। दुनिया उसे मिडल ईस्ट कहती है। पिछले दो महीने से वहां पर जो घटनाक्रम चल रहा है, उसका एक बहुत दूरगामी प्रभाव भारत की ऊर्जा सुरक्षा के ऊपर पड़ने वाला है। वहां पर परिस्थितियां बहुत ही तनावपूर्ण बनी हैं, खासकर जिसे स्ट्रेट ऑफ होरमुज़ कहते हैं, गल्फ ऑफ ओमान कहते हैं। जहां से 80 प्रतिशत दुनिया का कच्चा तेल, सागर के मार्ग से जाता है। वहां पर परिस्थितियां बहुत ज्यादा खतरनाक बनती जा रही हैं।

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि वर्ष 2018-19 में भारत ने ईरान से 23.5 मिलियन टन कूड इम्पोर्ट किया था, और भारत की रिफाइनरीज़ के लिए ईरान से जो कूड इम्पोर्ट किया जाता है, वह उनकी वर्किंग के लिए अनुकूल है। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह पूछना चाहता हूँ कि 2 मई, 2019 को अमेरिका ने भारत व कई अन्य देशों को जो वेवर दे रखा था कि अगर आप ईरान से तेल इम्पोर्ट करेंगे तो आपके ऊपर सैंक्शन नहीं लगाई जाएगी, वह वेवर हटा दिया गया है। अब, क्या सरकार ईरान से तेल इम्पोर्ट करती रहेगी और अगर इम्पोर्ट नहीं करेगी, तो सरकार ने और क्या व्यवस्था की है? भारत में जो तेल की कीमत है, मिट्टी के तेल और गैस की कीमत है, यह न बढ़े। सरकार को इसका जवाब देना चाहिए।

**माननीय अध्यक्ष:**

श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री मनीष तिवारी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

